भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव

डॉ. राजीव कुशवाहा
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर
विकासखण्ड – पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग)

शोध सारांश :–

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों में आस्था को पुनर्जीवित करना है तथा इसके लिए आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे प्राचीन मूल्यों, पैसे पंच महायज्ञ सोलह संस्कार, तीन ऋण, भारतीय आयुर्वेद पद्धति, सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देने वाली प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वेदों, उपनिषदों, पुराणों में निहित व्यावहारिक ज्ञान की अथाह सामग्री, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सम्यक् आकार देने वाली अष्टांग योग पद्धति, प्रकृति के प्रति भारतीय ग्रंथों में अद्‌भुत पोषण का दृष्टिकोण आदि के प्रति श्रद्धा व वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल शोध का दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि हम शारीरिक, मानसिक व नैतिक दृष्टिकोण से सम्मुनत होकर पुनः विश्व गुरु के रूप में स्वय को प्रतिस्थापित कर सके।

भारत को सदैव ''विश्वगुरु'' का दर्जा दिया गया है। हमें यदि यह अप्रतिम अलंकरण प्राप्त है तो निःसंदेह हमारी आधुनिक उपलब्धियों के कारण नहीं अपितु हमारी प्राचीन उन्नत, गौरवशाली संस्कृति तथा विज्ञान के कारण है। किसी भी श्रेष्ठ प्राचीन तथ्यों को प्राचीन व अप्रासंगिक कहकर उनका उपहास करना नहीं चाहिए, अपितु नूतन समय में वे तार्किक अनुपम तथ्य हमारे लिए किस प्रकार प्रासंगिक व कल्याणकारी हो सकते हैं, यह शोध का एक अत्युत्तम विषय है।

शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत–केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्परहै। शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इस शोधपत्र में शोधकर्ता द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित है शिक्षा नीति की वास्तविक मूक विशेषताओं को दर्शाना चाहता है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता, इस शोधपत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

मूलशब्द :–भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय परिवेश।

प्रस्तावना :—

नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा नीति बनाई थी, उस पर अमल चल रहा है। इसमें सांस्कृतिक चेतना के साथ आधुनिक विकास को महत्व दिया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़ा योगदान देगी। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय देश के युवाओं के लिए नए अवसर का सृजन करेगी। यह अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ भारत को अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक हब बनाने में सहायक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई कल्पना का सूत्रपात किया है। यह एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ी दृष्टि को रेखांकित करने वाली है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ—साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिएएक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है।इसका उद्देश्यधर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम औरशिक्षाशास्त्र को,छात्रोंमेंमौलिककर्तव्यों केप्रतिसम्मानकीभावनापैदाकरनीचाहिए औरसंवैधानिकमूल्यों,अपने देशऔरएक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों मेंभी विकास करना है,जो मानव अधिकारों, सतत् विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंवित होता है।

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ० राधाकृ

ष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।

अगस्त 1985 ''शिक्षा की चुनौती'' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने ''शिक्षा नीति 1986'' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे मान.राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व में जारी किया गया था।

इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति के लिये जनता से सलाह मांगना शुरू किया था।

आधुनिक युग में तकनीक व भौतिक सुविधाओं का खूब विकास हुआ। लेकिन विकास की दौड़ में सामाजिक व मानवीय संवेदनाओं का महत्व कम हुआ है। उपभोगवादी सभ्यता ने अनेक प्रकार की अन्य समस्याओं को भी जन्म दिया है। प्रकृति व पर्यावरण संबंधी संकट भी बढ़ रहा है। ऐसे में संतुलित विकास पर ध्यान देना अपरिहार्य हो गया है। यह कार्य पाश्चात्य सभ्यता के माध्यम से नहीं हो सकता। उन्हें तो अपनी समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनका चिंतन इसके अनुरूप नहीं है। जबकि भारत के प्राचीन ऋषियों मनीषियों का चिंतन शाश्वत है। यह आज भी प्रासंगिक है।

मात्र एक वर्ष में देश के बारह सौ से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों ने स्किल इंडिया से जुड़े कोर्सों की शुरुआत की है। अनेक भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव होगी। इंजीनियरिंग के कोर्स का इन भाषाओं में अनुवाद शुरू हो चुका है। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीबों का बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रमोट करने का काम शुरू हो गया है। शिक्षा में भाषा सभ्यता संस्कृति सामाजिक मूल्यों को समुचित स्थान मिल रहा है। ऐसी शिक्षा नीति ही राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण करती है। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू की गई शिक्षा राष्ट्रीय स्वाभिमान को हीनता में बदलने वाली थी। शिक्षा केवल बाबू बनाने के लिए होगी,तो उससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र का अपेक्षित लाभ नहीं हो सकता। मानवीय दृष्टिकोण का भाव भी होना चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमें मुख्य आकर्षण बहु–विषयकविश्वविद्यालयऔरकॉलेजहैं,जिसमेप्रत्येकजिले में या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनलरिसर्चफाउंडेशनविश्वविद्यालयोंऔरकॉलेजोंमेंउत्कृष्ट सहकर्मी–समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी ।

शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केन्द्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ताऔर जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससेनियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण औरउत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एकव्यापक ढांचा तैयार किया है। शिक्षा नीति2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करतीहै जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़नेके लिए तैयार करतीहैं जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार, शिक्षा नीति बहु–विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या–समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्यविशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्यमुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- भारतीय ज्ञान परंपराऔर शिक्षा नीति 2020 का मूल लक्ष्य और उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना
- शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करना।
- भारतीय ज्ञान परंपरा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाना।
- उचित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करके ड्रॉप–आउट को कम करना।
- शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही, छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- छात्रों की निगरानी करना और उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

यहअध्ययनपाठ्य,आलोचनात्मक,मूल्यांकनात्मक,वर्णनात्मक,विश्लेषणात्मकऔरव्याख्यात मकविधियोंकाउपयोगकरतेहुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में शिक्षा नीति 2020 केसंपूर्णअध्ययनपरभीध्यान केन्द्रित करताहै।इसमेंएमएलएहैंडबुकऑफरिसर्चके8वेंसंस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।

1. डेटा संग्रह

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गयाहै जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर–मूल जानकारी प्रदान करता है।माध्यमिकस्रोतोंमेंजीवनी,लेखककेकार्योंकेमहत्वपूर्णअध्ययन,शोधपत्रऔरशोधप्रबंध,शोधपुस्तकें,व यक्तिगतसाक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

अध्ययन का महत्व

वास्तविकतथ्योंपरआधारितइसअध्ययनकेनिष्कर्षसमाजकेहितमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभाएंगे।इ सअध्ययनक्षेत्रमेंपूर्व

अनुसंधानकीकमीकेकारणयहशोधमॉडलइसअध्ययनकेलिएप्रस्तावितहै ।शोधकर्ताइसवर्तमानअध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने मेंमदद करेगा। यह शोध शिक्षा नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा। यह संदर्भ सामग्री भी तैयार करेगा और आगे के अध्ययन के लिए गुंजाइश प्रदान करेगा।

साहित्य की समीक्षा

संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन सेप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलतीहै।

पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र ''भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।'' "भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजीक्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और साथ ही बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगेबढ़रहीहै ।हर उच्च शिक्षासंस्थानमेंगुणवत्ताफ्री–शिप्सऔरस्कॉलरशिपकेसाथयोग्यता–आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रूप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन, और निकायों को विनियमित करने मेंयोग्यता आधारित सिद्ध नेताओं, और प्रौद्योगिकी–आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व–घोषणा के आधार पर द्विवार्षिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी–2020 के 2030 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। संबद्ध कॉलेजों के वर्तमान नामकरण के साथ सभी उच्च शिक्षासंस्थान बहु–अनुशासनात्मक स्वायत्त कॉलेजों के रूपमें उनके नाम पर डिग्री देने कीशक्ति के साथ विस्तार करेंगेयाउनकेसंबद्धविश्वविद्यालयोंकेघटककॉलेजबनजाएंगे ।एकनिष्पक्षएजेंसीनेशनलरिसर्चफाउंडेशनबुनियादीविज्ञान,अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी।

अजय कुरियन और सुदीप बी चेंमना के शब्दों में, "शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यद्यपि

शिक्षानीतिनेस्कूलऔरकॉलेजकीशिक्षाकोसमानरूपसेप्रभावितकियाहै,यहलेखमुख्यरूपसेशिक्षा नीति2020और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केन्द्रित है। यह पत्र शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षा नीति में रीयल–टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी औरसमीक्षाढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। शिक्षा नीति2020 उच्च शिक्षाकेलिएएक निर्णायकक्षणहै।प्रभावीऔरसमयबद्धकार्यान्वयनहीइसेवास्तवमेंपथप्रदर्शक बना देगा।''

संबंधित नीतियाँ

कई समवर्ती नीतियां और दस्तावेज़ हैं जो एनईपी 2020 में मदद करेंगे। तालिका 1 इन नीतियों और दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने का प्रयास करती है।

तालिका 1: एनईपी 2020 के लिए प्रासंगिक नीतियां और समवर्ती दस्तावेज़

स. क्र.	नीति	विवरण
1	शिक्षा का अधिकार (आरटीई)	किसी भी आयु वर्ग और आर्थिक वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना
2	प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)	इसका उद्देश्य उन लड़कियों तक पहुंचना था, जहां संसाधनों तक पहुंचना ''सबसे कठिन'' है।
3	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	जमीनी स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का विकास करना।
4	साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा	साक्षर समाज का निर्माण करना और लक्ष्य है 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के गैर साक्षर और नवसाक्षर।
5	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	उच्च शिक्षा प्रणाली एवं संबंधित प्रक्रिया में बहुआयामी सुधार हेतु।
6	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	समतामूलक शिक्षा की सुरक्षा के लिए स्कूली शिक्षा का प्रमुख कार्यक्रम।
7	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा	माध्यमिक या उच्च शिक्षा में विकलांग/दिव्यांग छात्रों से उच्च नामांकन प्राप्त करना।

	(आईईडीएसएस)	
8	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)	मुख्य पहल प्राथमिक शिक्षा को पुनर्जीवित करना और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एकरूपीकरण करना है।
9	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, शिक्षा नीति 2020	संज्ञानात्मक विकास के लिए और बच्चों के चिंतनशील प्रक्रियात्मक विकास को सक्षम करने के लिए।

यह समझना आवश्यक था कि किस सरकार या राजनीतिक दल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। यह पेपर विभिन्न समय–सीमाओं, भारत के प्रधानमंत्रियों और प्रमुख शैक्षिक सुधारों (तालिका 2) के आधार पर जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है।

कार्यप्रणाली :–

कंप्यूटर–सहायता प्राप्त गुणात्मक डेटा विश्लेषण

तालिका 2 : समयरेखा, प्रधान मंत्री और नीति स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार

शिक्षा नीति समयरेखा	प्रधान मंत्री	शिक्षा नीति सुधार
1968	इंदिरा गांधी	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना
1986	राजीव गांधी	वयस्क शिक्षा और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण
1992	पी वी नरसिम्हा राव	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा
2005	मनमोहन सिंह	सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम
2016	नरेंद्र मोदी	लिंग भेदभाव को संबोधित करना, शैक्षिक न्यायाधिकरण का गठन, विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम
2020	नरेंद्र मोदी	व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना, नियामक तंत्र की शुरुआत करके सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान को प्रेरित करना, शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना, उच्च शिक्षा के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व, व्यावसायिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा में सुधार

यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। शिक्षा नीतिको स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केन्द्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षानीतिसेदेशकी उच्च शिक्षाप्रणालीपरसकारात्मकऔरदीर्घकालिकप्रभावपड़नेकीउम्मीदहै।यहतथ्यकिविदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु–विषयक संस्थान शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे सभी क्षेत्रों में नए सिरे सेध्यान केन्द्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी।

जैसे रिसर्च का एक मतलब ष्री–सर्चष होता है, यानी फिर से खोजना, वैसे ही हमें भी अपने पुराने रीति–रिवाजों और संस्कृति को, जो आज भी ज़िंदा हैं, फिर से ज़िंदा करना होगा और उन्हें असलियत में अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा।।

''भारत'' शब्द दो शब्दों 'भा+रत' से मिलकर बना है ''भा'' का अर्थ सदैव ज्ञान के प्रकाश से आलोकित या ज्ञान की रोशनी से चमत्कृत है, वही भारत है। हमारे प्राचीन संस्कार हमें धरती को माता मानकर उसका शोषण नहीं अपितु पोषण करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं– **माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः।**

आज जब पूरी दुनिया ''कोरोनावायरस'' की अनसुलझी मुसीबत से जूझ रही है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की उपयोगिता को पहचाना और समझा गया है कि कैसे हमारा पुराना ज्ञान और सांस्कृतिक ढांचा ऐसा है कि ऐसी समस्याएं पैदा ही नहीं होतीं। शुरू से ही भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करके लोगों का अभिवादन किया जाता रहा है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, प्रिंस चार्ल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की नमस्ते करते हुए एक तस्वीर सामने आई थी।

शिक्षा हमे पुनः प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति को जाग्रत करने की आवश्यकता है जो ''सा विद्या या विमुक्तये'' के सिद्धांत पर आधारित थी जबकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था केवल ''सा विद्या या वियुक्तय'' सिद्धांत पर आधारित हो चली है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित हो चली है, कृत्रिमता ही चहुँ और परिलक्षित होती है। हमे प्राचीन वैटिक शिक्षा प्रणाली, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों का शोध करना होगा द्य एक बात स्पष्ट है कि प्राचीन शिक्षा

प्रणाली को बर्तमान समय में यथावत् लागू नहीं किया जा सकता, किन्तु यह शोध का एक अत्यंत उपयोगी विषय हो सकता है कि प्राचीन सिद्धांतों को अपनाकर किस प्रकार शिक्षा को जानोन्मुख, मूल्यवान व रोजगारोन्मुख बनाया जा सके।

वास्तविक बच्चों का ज्ञान – हमारी प्राचीन परंपरा में इस विषय के शोध की विशेष आवश्यकता है कि वेद, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों आदि में कई तथ्यों को रुचिकर बनाने व समझाने के दृष्टिकोण से सांकेतिक रूप में कहा गया है, लेकिन हम उसका सीधा मतलब निकालकर उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं।

उपनिषद् व पुराण – उपनिषद् ज्ञान की अमूल्य निधि है। उपनिषदों में प्रतिपादित सृष्टि उत्पति सिद्धांत, तैत्तिरीय उपनिषद् का पंचकोश सिद्धांत, विभिन्न संवाद, आत्मा की जाग्रत, सुषुप्ति, स्वप्न व तुरीय अवस्थाएं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का वैज्ञानिक सिद्धांत, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, कर्म सिद्धांत आदि पर जितना शोध किया जाए उतनी ही नवीन व वैज्ञानिक अवधारणाएं प्राप्त होती है । भागवत पुराण के अनुसार–''जब संसार अन्धकार से उबरा तो जल में प्रारंभिक मूल प्रकृति से वनस्पति का बीज उत्पन्न हुआ, जिससे पौधों को जीवन मिला। पौधों से कीटाणु उत्पन्न हुए जो जीव अनुक्रम में कीड़े, सांप, कछुआ, पक्षी, पशु आदि अवस्थाओं से होते हुए मानव रूप प्राप्त किये। पौधों व जीवों की उत्पति का यह विशुद्ध वैदिक ज्ञान है।'' ऋषि मनु के अनुसार, ''सभी जीव अपनी पुरानी पीढ़ियों के जीवित रहने की क्षमता को अपनाकर आगे बढ़ते रहे।'' सोलहवीं सदी के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इसे ''डार्विन विकासवाद'' प्रणाली का नाम दिया।

उपसंहार

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्यन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की आज यह महती आवश्यकता का विषय है कि हमारी समस्त प्राचीन पम्मराएं यथा तिलक लगाना, कर्णवेध, मुंडन, समस्त संस्कार, गंगा में अस्थि विसर्जन, श्मशान कें पश्चात स्नान, आरती करना, घंटी बजाना, यज्ञाग्नि प्रज्वलित करना, शिखा रखना, चरणस्पर्श करना आदि के पीछे बड़ी–बड़ी वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, उनका शोध तथा कृत्त शोध को आगे बढ़ा युवा व बालपीढ़ी के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता है।भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटनेवालेविषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्तकरना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है,जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है।इसमें कोई सन्देहनहीं कि अगर शिक्षा नीति 2020को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आजाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ओड़, एल.के (2007) : शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रीमियर प्रन्टिंग प्रेस, जयपुर
2. अग्रवाल, पवन (2009) : श्रम बाजार के अनुरूप उच्च शिक्षा, योजना, अंक : 09 सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 11–13 .
3. चन्सौरिया, मुकेश (2009) : भारत में उच्च शिक्षा : समस्याएं एवं समाधान, योजना, अंक : 09, सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 27–30
4. पाण्डेय, हरेश (2007) : भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम का विकास, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, वर्ष 14 अंक–1, अप्रैल 2007, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 17 श्री अरविदों मार्ग, नई दिल्ली
5. फांसिस, सौदंराराज, (2001) : रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन इन इण्डिया, यूनिवर्सिटी न्यूज, 39(29), ए0आई0यू0 नई दिल्ली
6. भटनागर, आर0 पी0 एवं विद्या अग्रवाल, (2007) : शैक्षिक प्रशासन, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, लायल बुक डिपो, मेरठ
7. रहमान, सफी, (2008) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इंडिया टुडे 25 जून 2008, पृ0 20–21
8. सिंह,एल0सी0, (2003) : सेल्फ फाइनेसिंग हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी न्यूज 40,(40), ए0आई0यू0, नई दिल्ली
9. सारस्वत, मालती एवं बाजपेयी.बी.एल (1996) : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, आलोक प्रकाशन, लखनऊ
10. रिसर्च मैथ्डोलॉजी (डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, डॉ. डी.पी. शुक्ला) पृ.सं.– 24
11. मनुस्मृति 3 ⁄ 70
12. अथर्ववेद (12 ⁄ 1) ⁄ 12
13. वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश आधुनिक परिप्रेक्ष्य जपसकम चप (सम्पादक– डॉ मनोदत्त पाठक), पृ.सं.– 489
14. वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, पृ.स.– 553